

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2025—श्रावण 3, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जून 2025

क्रमांक ESTB/102(1)/62/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 18/11/2025-EO(MM-I), दिनांक 04-06-2025 के तारतम्य में श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निदेशक, राजस्व विभाग के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जून 2025

क्रमांक ESTB-102(2)/57/2025-GAD-4. —राज्य शासन एतद्वारा श्री हर्षवर्धन सिंह, अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 (56100-1,77,500) में संयुक्त विचार क्षेत्र सूची में इनके कनिष्ठ श्री छबीलाल ओटी, अधीक्षक, भू-अभिलेख का डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दिनांक 10-01-2018 से पदोन्नत करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उपायुक्त, आयुक्त कार्यालय, भू-अभिलेख, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ करता है. कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर पदोन्नत अधिकारी को वेतन अवशेष की पात्रता नहीं होगी. काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारित किया जायेगा. वास्तविक लाभ पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

2. उक्त पदोन्नति तीन वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए होगी तथा पदोन्नत अधिकारी की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगी.

3. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other's में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जून 2025

क्रमांक/2027/एफ-02/40/2013/14-2—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क से छूट नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
“(1) ये नियम “छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2019-24 के अंतर्गत मंडी शुल्क से छूट नियम, 2019” कहलायेंगे.”
- नियम 2 के खण्ड (ड) एवं (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(ड) **“विद्यमान उद्योग”** से अभिप्रेत है ऐसे समस्त उद्योग, जिन्होंने नियत दिनांक अर्थात् 01 नवम्बर, 2019 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो.

(ढ) **“विद्यमान उद्योग के विस्तार”** से अभिप्रेत है ऐसे उद्योग, जिन्होंने नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में मान्य निवेशित राशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त निवेश किया हो, जिससे उद्योग विभाग में पंजीकृत क्षमता या औसत उत्पादन (जो अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती हो, इसके अतिरिक्त विस्तारित क्षमता का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को अथवा उसके पश्चात् से 31 अक्टूबर, 2024 के मध्य हो. “विस्तारीकरण” की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व विद्यमान इकाई को सक्षम अधिकारी (जिसने इकाई को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया हो) से इस बाबत सूचना देकर विस्तार हेतु प्रस्तावित निवेश की निर्धारित मात्रा के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

3. नियम 2 के खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (न) अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(न) अन्य परिभाषाएं औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुसार मान्य होगी.”
4. नियम 3 के खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“(1) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कालावधि 01 नवम्बर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाले कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में आने वाले (औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) समस्त नवीन उद्योगों की स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाईयों को मण्डी शुल्क से छूट प्राप्त होगी.”
5. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“4. **मण्डी शुल्क से छूट की मात्रा —**
- 4.1 सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले नवीन/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से कच्चा माल क्रय करने पर मंडी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रु. 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75% से अधिक नहीं होगी.
- 4.2 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले नवीन/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से कच्चा माल क्रय करने पर मण्डी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रु. 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100% से अधिक नहीं होगी.”

यह अधिसूचना दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2160/1250/21-ब (एक)/छ.ग./2025. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री द्विज सिंह सेंगर (Shri Dwij Singh Sengar) पिता श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर, (UR-O-मेरिट क्र.-10) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2162/1243/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. सीमा नेताम (Ku. Seema Netam) पिता श्री ईश्वर सिंह नेताम, (ST-F-O, मेरिट क्र.-47) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2164/1513/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. भावना रिगरी (Ku. Bhawna Rigri) पिता श्री खिलावन राम रिगरी, (OBC-F, मेरिट क्र.-21) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2166/1242/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. आयुषी शुक्ला (Ku. Ayushi Shukla) पिता श्री सुशील शुक्ला, (UR-F, मेरिट क्र.-05) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2168/1334/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री तुषार बारिक (Shri Tushar Barik) पिता श्री आनंद बारिक, (OBC-O, मेरिट क्र.-29) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2170/1197/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सूरज राणा (Shri Suraj Rana) पिता श्री जितेन्द्र राणा, (UR-O, मेरिट क्र.-20) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2172/1411/21-ब (एक)/छ.ग./2025. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आदित्य जैन (Shri Aaditya Jain) पिता श्री नरेश कुमार जैन, (UR-O, मेरिट क्र.-13) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2174/1136/21-ब (एक)/छ.ग./2025. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री निखिल साहू (Shri Nikhil Sahu) पिता श्री भगवान सिंह साहू, (UR-O, मेरिट क्र.-03) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2176/1409/21-ब (एक)/छ.ग./2025. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. महिमा शर्मा (Ku. Mahima Shurma) पिता श्री देवेन्द्र शर्मा (UR-F, मेरिट क्र.-02) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2178/1532/21-ब (एक)/छ.ग./2025. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री क्षितिज नवरंग (Shri Kshitij Nawarang) पिता श्री ताम्रध्वज नवरंग (UR-O, मेरिट क्र.-16) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2180/1524/21-ब (एक)/छ.ग./2025. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. निशी बड़ा (Ku. Nishi Bara) पिता स्व. श्री पिटर बड़ा (ST-F-O, मेरिट क्र.-37) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2182/1249/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. रिया गणवीर (Ku. Riya Ganvir) पिता श्री राजेश गणवीर (SC-F-O, मेरिट क्र.-43) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2184/1476/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. आरती ध्रुव (Ku. Aarti Dhruw) पिता श्री दीनबंधु ध्रुव (UR-F, मेरिट क्र.-08) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2186/1516/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. अंजिता खुटे (Ku. Anjeeta Khutey) पिता श्री धनाराम खुटे (SC-F-O, मेरिट क्र.-27) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2188/1245/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जितेन्द्र कुमार सोनवानी (Shri Jitendra Kumar Sonwani) पिता श्री महेश कुमार सोनवानी (SC-O, मेरिट क्र.-41) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 मार्च 2025

क्रमांक एफ 12-1/2022/मबावि/50.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2022 द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के तहत प्रवर्तकता कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु “छत्तीसगढ़ राज्य प्रवर्तकता कार्यक्रम क्रियान्वयन दिशा निर्देश, 2022” जारी किये गये थे.

भारत शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पत्र क्रमांक D.O No. CW-II-22/06/2022 दिनांक 05-07-2022 द्वारा मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण योजना) के क्रियान्वयन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार मिशन वात्सल्य मानदंड 01 अप्रैल 2022 से लागू है. विभागीय पत्र क्रमांक 7688/मबावि/एससीपीएस दिनांक 22-11-2022 द्वारा 01 अप्रैल 2022 से मिशन वात्सल्य मानदंड लागू होने की स्वीकृति जारी की गई है.

अतः उपरोक्त के प्रकाश में राज्य शासन एतद्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य प्रवर्तकता कार्यक्रम क्रियान्वयन दिशा निर्देश, 2022” में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

अर्थात् :—

उक्त दिशा-निर्देश में,—

निर्देश की कंडिका क्रमांक 5.अ.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

भारत शासन द्वारा जारी मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देश दिनांक 05-07-2022 के प्रावधानानुसार प्रवर्तकता हेतु बालकों का चयन जिनके परिवार की वार्षिक आय निम्न से अधिक न हो—

- (अ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72,000/- रुपये वार्षिक
- (ब) अन्य क्षेत्रों के लिए 96,000/- रुपये वार्षिक

निर्देश की कंडिका 6.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है —

पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के बच्चों को प्रति बालक रुपये 4,000/- अथवा तत्समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी.

निर्देश की कंडिका 6.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है —

किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति या बाल न्यायालय द्वारा लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों के आधार पर यह सहायता बालक/बालिका की आयु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रदान की जा सकेगी. प्रवर्तकता सहायता की अवधि मिशन वात्सल्य कार्यक्रम के संचालन की अवधि से अधिक नहीं होगी. प्रवर्तकता की समाप्ति से पूर्व परिवार को बच्चों की देखरेख करने हेतु आर्थिक एवं अन्य रूप से सशक्त बनाये जाने के प्रयास किये जायेंगे. प्रवर्तकता एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) समय-समय पर प्रवर्तकता प्रकरणों की समीक्षा करेगी.

निर्देश की कंडिका 7 में उल्लेखित प्रवर्तकता एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है —

क्र.	सदस्यगण	पदनाम
1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति	सदस्य
3.	विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएए) के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	सदस्य सचिव
6.	संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखभाल)	सदस्य

निर्देश की कंडिका 8.अ.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है —

8.अ.5 गृह अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रवर्तकता एवं पालन-पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) की मासिक बैठक में प्रकरणों को विचारार्थ रखेगा। प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों यथा बालक का जीवन वृत्त, व्यक्तिगत देखरेख योजना, सामाजिक जांच रिपोर्ट/सामाजिक पृष्ठ भूमि रिपोर्ट, गृह अध्ययन रिपोर्ट आदि की संवीक्षा/जांच उपरांत यदि बालक का प्रकरण प्रवर्तकता हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो समिति तदनुसार अपनी अनुशंसा करेगी। समिति (SFCAC) द्वारा अनुशंसित प्रवर्तकता प्रकरण जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्तानुसार अनुशंसित प्रवर्तकता प्रकरण बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड बाल न्यायालय को प्रेषित किये जावेंगे। जिला मजिस्ट्रेट बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदन देंगे या प्रकरण की समीक्षा के लिए संदर्भित करेंगे। समिति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा कर उनके प्रतिक्रिया दे सकती है। जिला मजिस्ट्रेट अनुशंसा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

निर्देश की कंडिका 8.ब.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है —

8.ब.4 गृह अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रवर्तकता एवं पालन-पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) की मासिक बैठक में प्रकरणों को विचारार्थ रखेगा। प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों यथा बालक का जीवन वृत्त, व्यक्तिगत देखरेख योजना, सामाजिक जांच रिपोर्ट/सामाजिक पृष्ठ भूमि रिपोर्ट, गृह अध्ययन रिपोर्ट आदि की संवीक्षा/जांच उपरांत यदि बालक का प्रकरण प्रवर्तकता हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो समिति तदनुसार अपनी अनुशंसा करेगी। समिति (SFCAC) द्वारा अनुशंसित प्रवर्तकता प्रकरण जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्तानुसार अनुशंसित प्रवर्तकता प्रकरण बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड बाल न्यायालय को प्रेषित किये जावेंगे। जिला मजिस्ट्रेट बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदन देंगे या प्रकरण की समीक्षा के लिए संदर्भित करेंगे। समिति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा कर प्रतिक्रिया दे सकती है। जिला मजिस्ट्रेट अनुशंसा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

कंडिका- 11.3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :—

बच्चे ने स्कूल अथवा आंगनबाड़ी अथवा प्रशिक्षण संस्था में जाना बंद कर दिया हो। (केवल उन विशेष परिस्थितियों में जब कि बच्चा बीमार हो/निःशक्त हो, निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा, जिसका जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सत्यापन कराया जाएगा तथा मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की जावेगी।)

उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2022 से लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जून 2025

क्रमांक ESTB/4033/2025-FOOD.—विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक F. No. 2696/1950/XXI-B/C.G./2025 दिनांक 23-06-2025 द्वारा छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री श्रीनिवास तिवारी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कवर्धा की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपते हुए रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर के पद पर की गयी है।

2. अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री श्रीनिवास तिवारी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कवर्धा को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर****नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 जून 2025**

क्रमांक 1444/एफ 1-3/2023/CSERC/13/1.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक 576/एफ-1-3/2024/CSERC/13/1 दिनांक 27-02-2025 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन. 2003) की धारा-85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति हेतु पैनल की अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, समिति के अनुशंसा पर विचारोपरांत, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा-82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजय कुमार सिंह, S/o स्व. श्री एस. पी. सिंह, मुख्य अभियंता (उपकेन्द्र), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है।

3. श्री अजय कुमार सिंह की नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी।

4. श्री अजय कुमार सिंह को देय वेतन एवं भत्ते, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य की सेवा शर्तें हेतु समय-समय पर जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रशासित रहेगा।

5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 जून 2025

क्रमांक 1446/एफ 1-3/2023/CSERC/13/1.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक 576/एफ-1-3/2024/CSERC/13/1 दिनांक 27-02-2025 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन. 2003) की धारा-85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति हेतु पैनल की अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, समिति के अनुशंसा पर विचारोपरांत, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा-82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विवेक गनोदवाले, S/o स्व. श्री मुरलीधर गनोदवाले, अधिवक्ता, 7, उद्यान मार्ग, चौबे कॉलोनी, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य (विधि) नियुक्त करता है।

3. श्री विवेक गनोदवाले की नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए होगी।

4. श्री विवेक गनोदवाले को देय वेतन एवं भत्ते, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य (विधि) की सेवा शर्तें हेतु समय-समय पर जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रशासित रहेगा।

5. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष कुमार जायसवाल, उप-सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 2 जून 2025

प्र. क्रमांक 05/अ-82/2020-21/1702.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के डुबान कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् में अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 की उपधारा-07 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ के राजपत्र में दिनांक 08-01-2025 को प्रकाशित किया गया था। किंतु उक्त प्रकरण में धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका। प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनः 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि की वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है।

अनुसूची					धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल			
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल खसरा	कुल रकबा (हे.) में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	करगीकला, प.ह.नं. 24	01	0.709	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डुबान कार्य का भू-अर्जन.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 2 जून 2025

प्र. क्रमांक 05/अ-82/2020-21/1704.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के डुबान कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् में अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 की उपधारा-07 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ के राजपत्र में दिनांक 08-01-2025 को प्रकाशित किया गया था। किंतु उक्त प्रकरण में धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका। प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनः 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि की वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है।

अनुसूची					धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल			
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल खसरा	कुल रकबा (हे.) में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	परासी प.ह.नं. 6	16	0.891	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डुबान कार्य का भू-अर्जन.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 6 जून 2025

प्र. क्रमांक 05/अ-82/2020-21/1778.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के डुबान कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् में अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 की उपधारा-07 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ के राजपत्र में दिनांक 08-01-2025 को प्रकाशित किया गया था. किंतु उक्त प्रकरण में धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनः 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि की वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची					धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल			
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल खसरा	कुल रकबा (हे.) में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	धनौरा प.ह.नं. 31	01	0.097	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डुबान कार्य का भू-अर्जन.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लीना कमलेश मंडावी , कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.						

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10 जून 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/2170.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6154-6155 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री शशांक शिंदे, उप संचालक कृषि, जिला सक्ती को कृषि उपज मंडी समिति सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कृषि उपज मंडी समिति सक्ती, जिला सक्ती के भारसाधक अधिकारी श्री शशांक शिंदे, उप संचालक कृषि, जिला सक्ती के स्थान पर श्री पदमलोचन पटेल नायब तहसीलदार कार्यालय कलेक्टर सक्ती को कृषि उपज मंडी समिति सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री शशांक शिंदे, उप संचालक कृषि, जिला सक्ती के स्थान पर श्री पदमलोचन पटेल नायब तहसीलदार कार्यालय कलेक्टर सक्ती (छ.ग.) को कृषि उपज मंडी समिति सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th May 2025

No. 381/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column no. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Santosh Kumar Aditya Director, Chhattisgarh State Judicial Academy	Bilaspur	Korba	Korba	I District and Additional Sessions Judge.

Bilaspur, the 7th May 2025

No. 387/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following Civil Judges Senior Division, as specified in Column no. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Aslam Khan, Civil Judge Senior Division	Champa	Raipur	Raipur	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division
2.	Ku. Akansha Rathore, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Kawardha at Pandariya	Pandariya	Durg	Durg	IV Civil Judge Senior Division
3.	Ku. Namrata Norge, Law Officer, Chhattisgarh Human Rights Commission	Raipur	Champa	Janjgir- Champa	Civil Judge Senior Division
4.	Smt. Soni Tiwari, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Balod at Dallirajhara	Dallirajhara	Korba	Korba	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Shri Alok Kumar Agrawal, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division	Raipur	Pandariya	Kabirdham (Kawardha)	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division Kawardha at Pandariya
6.	Shri Rahul Kumar, Secretary, District Legal Services Authority	Kawardha	Dallirajhara	Balod	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Balod at Dallirajhara
7.	Smt. Kaminee Verma, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Jashpur at Bagicha	Bagicha	Raipur	Raipur	V Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division,

Note :— The Judicial Officers, whose name(s) are mentioned at serial nos. 1 and 7 above, shall not be entitled to any transfer grant and/or allowance(s) pursuant to transfer on his/her own request.

Bilaspur, the 7th May 2025

No. 393/Confdl./2025/II-2-3/2002 (Pt. IV).—The following District Judges (Entry Level), as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, appointed to the category of District Judge (Selection Grade) in the pay-Scale of Rs. 1,63,030-2,19,090 from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer with designation	Date of appointment to the category of District Judge (Selection Grade)
(1)	(2)	(3)
1.	Ku. Mohani Kanwar, District and Additional Sessions Judge, Khairagarh	07-05-2025
2.	Smt. Pallavi Tiwari, IX District and Additional Sessions Judge, Raipur	07-05-2025
3.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, VI District and Additional Sessions Judge, Raigarh	07-05-2025
4.	Smt. Urmila Gupta, Member Judge, Industrial Court, Raipur	07-05-2025
5.	Shri Balaram Sahu, District and Additional Sessions Judge, Gariaband	07-05-2025
6.	Shri Dilesh Kumar Yadav, District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Raigarh	07-05-2025
7.	Shri Leeladharsai Yadav, Member Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur	07-05-2025
8.	Shri Rakesh Kumar Som, I District and Additional Sessions Judge, Mungeli	07-05-2025
9.	Shri Kamlesh Kumar Jurri, Presiding Officer, Chhattisgarh State Wakf Tribunal, Raipur	07-05-2025

(1)	(2)	(3)
10.	Shri Anand Prakash Dixit, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur	07-05-2025
11.	Ku. Radhika Saini, District and Additional Sessions Judge, Sarangarh	07-05-2025
12.	Shri Shailendra Chauhan, I District and Additional Sessions Judge, Janjgir-Champa	07-05-2025
13.	Smt. Jyoti Agrawal, District and Additional Sessions Judge, Pendra Road	07-05-2025
14.	Shri Achchhey Lal Kachhi, District and Additional Sessions Judge, I F.T.S.C. (POCSO), Raipur	07-05-2025
15.	Ku. Udai Laxmi Parmar, Chairman, Permanent Lok Adalat, Jagdalpur	07-05-2025
16.	Smt. Kiran Tripathi, III District and Additional Sessions Judge, Bilaspur	07-05-2025
17.	Ku. Smita Ratnawat, V District and Additional Sessions Judge, Ambikapur	07-05-2025
18.	Shri Amit Rathore, District and Additional Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO), Sarangarh	07-05-2025
19.	Shri Anil Kumar Pandey, II District and Additional Sessions Judge, Mahasamund	07-05-2025
20.	Smt. Vibha Pandey, I District and Additional Sessions Judge, Kanker	07-05-2025
21.	Smt. Kiran Thawait, X District and Additional Sessions Judge, Raipur	07-05-2025
22.	Shri Ashok Kumar Lal, Additional Judge to the Court of District and Additional Sessions Judge, Bhatapara	07-05-2025
23.	Shri Sumit Kapoor, Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur	07-05-2025
24.	Shri Awadh Kishore, District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Durg	07-05-2025
25.	Shri Jitendra Kumar Singh, II District and Additional Sessions Judge, Raipur	07-05-2025
26.	Shri Shailesh Sharma, III District and Additional Sessions Judge, Raipur	07-05-2025
27.	Shri Vikram Pratap Chandra, District and Additional Sessions Judge, Kondagaon	07-05-2025
28.	Shri Krishn Pal Singh Bhadauriya, Deputy Secretary, Chhattisgarh Lok Ayog, Raipur	07-05-2025
29.	Shri Sanjay Agarwal, XIV District and Additional Sessions Judge, Raipur	07-05-2025
30.	Shri Santanoo Kumar Deshlahre, District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Raipur	07-05-2025
31.	Shri Avinash Kumar Tripathi, District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Ambagarh Chowki	07-05-2025

By order of the High Court,
K. VINOD KUJUR, Registrar General.